भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *240
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2019

मोबाइल टॉवर

***240. श्री राहुल रमेश शेवाले; श्री भर्तृहरि महताबः**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों में गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 2199 स्थानों पर मोबाइल टॉवर संस्थापित करने हेतु कोई योजना अनुमोदित की है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे टॉवरों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना की लागत कितनी है तथा योजना के आरंभ होने के उपरान्त से ऐसे टॉवर के संस्थापन हेतु बीएसएनएल को भारत सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार/बीएसएनएल उक्त स्थानों पर मोबाइल टॉवरों के संस्थापन में योजना में निर्धारित लक्ष्य से पीछे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधरात्मक कदम उठाए हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से (घ) विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

जारी..2/-

'मोबाइल टावर' के बारे में लोक सभा के दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 के तारांकित प्रश्न संख्या *240 के भाग (क) से (घ) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) मंत्रिमंडल ने दिनांक 20.08.2014 को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 10 राज्यों (तेलंगाना राज्य बनने से पूर्व 9 राज्यों) में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में अभिनिर्धारित 2199 स्थानों पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया। इस कार्य को बीएसएनएल द्वारा नामांकन आधार पर किया गया था।

तत्पश्चात, गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 156 अतिरिक्त स्थानों की पहचान की थी, जिन्हें जून 2016 में अनुमोदित कर दिया गया था।

एलडब्ल्यूई चरण-I का राज्य-वार ब्योरा **अनुबंध-I** में दिया गया है:

(ख) एलडब्ल्यूई चरण-I की परियोजना लागत 4214.30 करोड़ रू. है और दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार 2830.20 करोड़ रू. संवितरित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ): मार्च 2017 में 2199 टावर स्थलों पर तथा दिनांक 01.11.2018 तक 156 अतिरिक्त स्थलों पर टावर लगाने और इन्हे चालू करने का कार्य पूरा हो चुका है और ये कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना में सदूर और कठोर भू-क्षेत्र, राज्य सरकारों द्वारा कुछ स्थल उपलब्ध कराने में विलम्ब, स्थलों में बदलाव आदि के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा कारणो और नक्सली गतिविधियों के कारण राज्य सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कुछ स्थानों पर कार्य नहीं किया जा सका। अब 2343 स्थलों पर सेवाएं चालू हैं।

जारी–3/-

अनुबंध-I

"मोबाइल टावर" के संबंध में माननीय संसद सदस्य राहुल रमेश शेवाले, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा लोक सभा में दिनांक 04 दिसम्बर 2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *240 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एलडब्ल्यूई-I की स्थिति

क्र.सं.	**राज्य**	**एमएचए द्वारा अभिनिर्धारित कुल स्थानों की सं.**	**अतिरिक्त 156 स्थल**	**एलडब्ल्यूई चरण-I के तहत कुल स्थल**	**वर्तमान स्थिति (कार्य कर रहे)**
1	आंध्र प्रदेश	54	8	62	62
2	बिहार	184	66	250	250
3	छत्तीसगढ़	497	35	532	525
4	झारखंड	782	34	816	816
5	महाराष्ट्र	60	5	65	65
6	मध्य प्रदेश	22	0	22	22
7	ओडिशा	253	8	261	256
8	तेलगांना	173	0	173	173
9	उत्तर प्रदेश	78	0	78	78
10	पश्चिम बंगाल	96	0	97	96
	कुल	**2,199**	**156**	**2355***	**2343***

* सुरक्षा कारणों और नक्सली गतिविधियों के कारण 12 टावरों से सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकी।

*****